Publication	The Hindu Business Line	Language	English
Edition	Mumbai	Journalist	Prabhudatta Mishra
Date	19/10/2023	Page no	10
CCM	50.71		

Ready to collaborate on G2G deals, procure from FPOs, rice exporters tell Co-op Ministry

Ready to collaborate on G2G deals, procure from FPOs, rice exporters tell Co-op Ministry

Prabhudatta Mishra
New Delhi

Exporters of non-Basmati rice have requested the government to identify those firms who have consistently paid Minimum Support Price (MSP) to paddy farmers and declare them as the "preferred counterparties" for export collaborations.

The request has come after the Centre appointed the newly-created National Cooperative Exports Ltd as the canalising agency for government-to-government deals.

In a letter to the Cooperation Ministry, The Rice Exporters Association (TREA) said it appreciates the government's initiative in promoting rice exports, which are under prohibition, through Cooperatives for other countries' requirements. However, as millers and exporters have made significant investments in creating manufacturing facilities, they too want to be considered in execution of the overseas orders.

The association said it is ready to source rice from farmers' producers organisation in view of the Centre's objective of allowing NCEL to handle government-to-government (G2G) deals. "We are eager to collaborate and actively participate in the execution of these overseas orders. If acceptable, we are open to signing back-to-back contracts with an overriding commission to cooperatives, similar to the practice with other state-run organisations," TREA said in a letter to Union Cooperation Secretary Gyanesh Kumar.

WORKERS HURT

The exporters' body has proposed a joint meeting of related agencies/organisations such as APEDA and the Cooperation Ministry with its members to take the initiative forward.

"Such a meeting would provide an opportunity for open dialogue, collaboration, and establishment of a clear path forward that aligns with the goals of all stakeholders," it said. Highlighting that the exporters and millers employ thousands of workers in each major unit, the current ban on non-Basmati exports is impacting lakhs of workers.

The government has allowed only parboiled rice in the non-Basmati category with 20 per cent export duty; which recently got extended until March 31, 2024.

The industry body has also said its members have consistently exported an average of 10 million tonnes annually over the past five years, whereas cooperatives, collectively, have not achieved even 10,000 tonnes annually.

"For the efficient distribution of overseas orders, it seems logical and fair to consider past performance as the basis," TREA President BV Krishna Rao said in the letter.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Rajasthan Patrika	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	19/10/2023	Page no	4
CCM	62.64		

Liquid urea will increase crop production by 24%, conventional 70% is wasted

जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक डॉ. रमेश रलिया ने तैयार किया तरल नैनो यूरिया, इससे 2030 तक भारत के बचेंगे 40 बिलियन डॉलर

तरल यूरिया से 24% बढ़ेगा फसल उत्पादन, पारंपरिक 70% होता है बर्बाद

तरल नैनो यूरिया 14 मिलियन टन सब्सिडी वाले यूरिया की लेगा जगह

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नागौर. जोधपुर के छोटे से गांव खारिया खंगार से निकले युवा कृषि वैज्ञानिक का आविष्कार कृषि के लिए वरदान साबित होगा। 12वीं तक सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी तक पहुंचे एक किसान के बेटे नैनो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक डॉ. रमेश रलिया का तरल नैनो यूरिया आविष्कार न केवल भारतीय कृषि बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी बदल सकता है। डॉ. रलिया ने बताया कि पारंपरिक यूरिया को मिट्टी में दानेदार रूप में डालने के बजाय पेटेंटेड नैनो यूरिया को तरल रूप में फसल के दो प्रमुख विकास चरणों के दौरान सीधे पत्तियों पर छिड़का जा सकता है। अति-छोटे कण मिट्टी की तुलना में सीधे पत्ती से बेहतर अवशोषित होते हैं। मिट्टी में डाले जाने वाले पारंपरिक यूरिया का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पौधों की ओर से अवशोषित नहीं हो पाता और बर्बाद हो जाता है। यह मिट्टी को अम्लीय बनाता है और पानी का बहाव जल निकायों को प्रदूषित करता है। वहीं तरल नैनो यूरिया अनाज में फसल उत्पादकता को 24 प्रतिशत और फलों और सब्जियों में 8 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। गत दिनों नागौर दौरे पर आए डॉ. रलिया से पत्रिका ने विशेष बातचीत की। **पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश...**

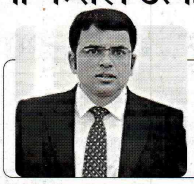

Q देश के किसानों को सस्ता यूरिया मिले, इसके लिए आपने क्या किया?

जवाब : बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मुझे नैनो यूरिया के पेटेंट के लिए 10 मिलियन डॉलर और 3 लाख डॉलर के वार्षिक वेतन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने अपने आविष्कार को बिना किसी टेक्नोलॉजी फीस के भारत सरकार के मार्फत इफको को लाइसेंस देने का फैसला किया, जो देश की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति है। भारतीय किसानों की कम लागत पर पोषक तत्वों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार के समक्ष एक ही शर्त थी कि नैनो फर्टिलाइजर-नैनो यूरिया किसानों को लागत मूल्य पर या सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

Q आपने तरल रूप में नैनो यूरिया तैयार किया है, इससे क्या फायदा होगा?

जवाब: मैंने अब तक अकार्बनिक और कार्बनिक नैनो कणों के संश्लेषण पर बीस से अधिक पेटेंट तैयार किए हैं। तरल रूप में नैनो यूरिया के आविष्कार से न केवल भारत को आयात और उर्वरक सब्सिडी में करीब 40 बिलियन डॉलर की बचत करने में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि उपज में भी सुधार होगा। कृषि रसायनों से पारिस्थितिक नुकसान भी रोका जा सकेगा।

Q यह यूरिया बाजार में अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्या किया जा रहा है?

जवाब : तरल नैनो यूरिया का आविष्कार किए दो साल ही हुए हैं। इसलिए शुरुआती चरण है। इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए अब निजी कम्पनियां भी प्लांट लगा रही हैं। इफको भी 8 प्लांट तैयार कर रहा है। जल्द ही उपलब्धता सुगम हो जाएगी।

Q नैनो यूरिया के तरल रूप से फसलों को क्या फायदा होगा?

जवाब : पारंपरिक यूरिया के बजाय तरल यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़कने से बेहतर अवशोषित होता है। मिट्टी में डाले जाने वाले पारंपरिक यूरिया का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पौधों की ओर से अवशोषित नहीं हो पाता और बर्बाद हो जाता है। तरल नैनो यूरिया लगभग 14 मिलियन टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह ले सकता है, जिससे 2030 तक देश को लगभग 40 बिलियन डॉलर के आयात की बचत होगी। साथ ही रसद और भंडारण लागत में भी काफी कमी आएगी।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD